



Daily करेंट अफेयर्स

» 23 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में DSCI उन्नत साइबर कौशल केंद्र का उद्घाटन किया।



19 जुलाई 2025 को, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के कांदिवली पूर्व में DSCI उन्नत साइबर कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (DSCI) द्वारा विकसित और किड्रिल फाउंडेशन द्वारा समर्थित, इस केंद्र का लक्ष्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत प्रतिवर्ष लगभग 1,000 युवाओं को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण देना है।

- इस केंद्र की शुरुआत टियर-II और टियर-III शहरों की महिलाओं और छात्राओं को सशक्त बनाने, साइबर सुरक्षा में लैंगिक अंतर को पाटने और वंचित समुदायों को डिजिटल नौकरी के अवसरों तक पहुंच प्रदान करने के लक्ष्य के साथ की गई थी।

- साइबर वाहिनी के नाम से जाना जाने वाला 28 इंजीनियरिंग स्नातकों का पहला समूह वर्तमान में नैतिक हैकिंग, खतरे की पहचान और घटना प्रतिक्रिया पर चार महीने के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजर रहा है।

- अत्याधुनिक साइबर रेंज, लाइव साइबर अटैक सिमुलेटर और उद्योग जगत के पेशेवरों के मार्गदर्शन से सुसज्जित, यह केंद्र हर साल लगभग 1,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करेगा। पाठ्यक्रम

PMKVY के तहत राष्ट्रीय कौशल लक्ष्यों के अनुरूप है और वैश्विक साइबर सुरक्षा प्रतिभा केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा का समर्थन करता है।

Key Points:-

(i) इस कार्यक्रम में बोलते हुए, पीयूष मंत्री गोयल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि साइबर सुरक्षा न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता है, बल्कि रोज़गार और नवाचार का एक प्रमुख वाहक भी है। यह केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य हैकर्स को अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करना, "हैक-टू-हेल्प" को बढ़ावा देना और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार भूमिकाओं के लिए तैयार करना है।

(ii) यह पहल साइबर सुरक्षा पेशेवरों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने के लिए DSCI के व्यापक प्रयास का हिस्सा है—जिसे किड्रिल फाउंडेशन का समर्थन प्राप्त है। DSCI ने पहले भारत, सिंगापुर, दुबई और रियाद में सम्मेलन आयोजित किए हैं और कौशल आदान-प्रदान तथा क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए आगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की योजना बना रहा है।

(iii) इस लॉन्च कार्यक्रम में विनायक गोडसे (CEO, DSCI), ऊना पुलिज़ी (कॉर्पोरेट मामलों की वैश्विक प्रमुख, किड्रिल), लिंगराजू सावकर (अध्यक्ष, किड्रिल इंडिया), और उत्तरी मुंबई के विधायकों तथा CII के अधिकारियों सहित कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति ने एक साइबर-लचीले और समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया।

INTERNATIONAL

1. भारत 2024 में मलेशिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक बनकर उभरा, जिससे खाद्य तेल मिशन को बढ़ावा मिला।



21 जुलाई, 2025 को, मलेशियाई पाम ऑयल बोर्ड (MPOB) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि भारत 2024 में मलेशिया से अंकुरित पाम तेल के बीजों का सबसे बड़ा आयातक बन गया। यह विकास खाद्य तेलों के आयात को कम करने और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP) के तहत घरेलू खेती को बढ़ावा देने के भारत के रणनीतिक प्रयासों के अनुरूप है।

- भारत ने 2024 में मलेशिया से 3.03 मिलियन टन (MT) पाम तेल का आयात किया, जिससे यह मलेशियाई पाम तेल निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य बन गया। यह मात्रा मलेशिया के कुल पाम तेल निर्यात का 17.9% थी। आयात में यह वृद्धि भारत की पाम तेल बीजों की बढ़ती माँग को दर्शाती है जो उसकी विस्तारित पाम खेती रणनीति का समर्थन करती है।

- भारत का आयात NMEO -ऑयल पाम के तहत निर्धारित लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है, जो खाद्य तेल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 2021 में शुरू किया गया एक मिशन है।

- इस मिशन का लक्ष्य 2025-26 तक पाम ऑयल की खेती को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है, और 2029-30 तक 28 लाख टन कच्चे पाम ऑयल का उत्पादन लक्ष्य है। इन लक्ष्यों का उद्देश्य खाद्य तेल आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य टोकरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Key Points:-

(i) अब तक, भारत ने लगभग 370,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पाम ऑयल की खेती शुरू कर दी है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों को उनकी उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण प्राथमिकता दी जा रही है, जो पाम ऑयल की खेती के लिए आदर्श है। अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और असम जैसे राज्य क्षेत्रीय विस्तार के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

(ii) मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों की थोक खरीद घरेलू उत्पादन क्षमता में सुधार की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। इससे न केवल बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित होगी, बल्कि योजना के तहत नामांकित किसानों के लिए रोपण सामग्री की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। इस कदम से ग्रामीण रोज़गार और किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ दीर्घकालिक खाद्य तेल सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

(iii) NMEO-OP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह नर्सरी विकास, बीज खरीद, प्रसंस्करण इकाइयों और अनुसंधान एवं विकास के लिए किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह पहल वैश्विक आयात पर निर्भरता कम करने और एक स्थायी खाद्य तेल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के भारत के "आत्मनिर्भर भारत" दृष्टिकोण के अनुरूप है।

BANKING & FINANCE

1. सरकार ने 'एक राज्य-एक RRB' नीति के तहत RRB का समेकन पूरा कर लिया है, जिससे संख्या घटकर 28 हो गई है।



1 मई 2025 को, भारत सरकार ने अपनी 'एक राज्य-एक RRB' नीति लागू की, जिसके तहत 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की संख्या 43 से घटाकर 28 कर दी गई। इस सुधार का उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग दक्षता में सुधार, लागत में कमी और देश भर में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

- यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत 2006 के बाद से RRB समेकन का चौथा चरण है। प्रारंभ में, RRB की संख्या 196 (2006) से घटकर 43 (2021) हो गई; अब चरण IV में सुव्यवस्थित संचालन और मजबूत शासन का समर्थन करने के लिए उन्हें घटाकर 28 कर दिया गया है।

- इस विलय से 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) अब 28 एकीकृत बैंकों में समेकित हो गए हैं, जो 22,000 से ज्यादा शाखाओं के माध्यम से 700 जिलों में सेवा प्रदान करते हैं, जिनमें से लगभग 92% ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। अब प्रत्येक राज्य में एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) इकाई है।

- प्रत्येक नए RRB को 2,000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी प्रदान की गई है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को ऋण देने के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार उपलब्ध होगा, साथ ही ग्रामीण भारत में ऋण की गहन पहुंच को बढ़ावा मिलेगा।

Key Points:-

(i) 28 पुनर्नामित और एकीकृत RRBs में नवगठित बैंक शामिल हैं, जैसे आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, गुजरात ग्रामीण बैंक, कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक और ओडिशा ग्रामीण बैंक, जो सभी अपने-अपने राज्यों में कई पूर्ववर्ती RRBs से स्थापित किए गए हैं।

(ii) डिजिटल परिवर्तन जारी है: NABARD ने ग्रामीण भारत में उन्नत डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और वित्तीय समावेशन प्रदान करने के लिए 15 सितंबर 2025 तक विलय किए गए RRB के लिए पूर्ण IT एकीकरण और नई प्रौद्योगिकी स्टैक रोलआउट को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

2. SBI रिसर्च रिपोर्ट में पाँच राज्यों पर प्रकाश डाला गया है जो सक्रिय GST करदाताओं में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान देते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है।



जुलाई 2025 में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के आर्थिक अनुसंधान प्रभाग, SBI रिसर्च ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) की आठवीं वर्षगांठ के अवसर पर एक शोध रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बताया गया कि पाँच भारतीय राज्य सामूहिक रूप से लगभग 50% सक्रिय GST करदाताओं का योगदान करते हैं। इन राज्यों में

उत्तर प्रदेश (UP) सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा।

- उत्तर प्रदेश (UP) भारत के सभी सक्रिय GST करदाताओं में 13.2% का योगदान देकर इस सूची में सबसे आगे है, जो महाराष्ट्र (12.1%), गुजरात (8.4%), तमिलनाडु (7.7%) और कर्नाटक (6.9%) से आगे है। ये पाँच राज्य अकेले देश के पंजीकृत जीएसटी करदाताओं का लगभग आधा हिस्सा हैं, जो कर गतिविधि में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संकेंद्रण का संकेत देता है।

- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये शीर्ष 5 राज्य सामूहिक रूप से भारत के सकल GST राजस्व में 41% का योगदान करते हैं। इसके अलावा, 6 राज्यों ने व्यक्तिगत रूप से जीएसटी संग्रह में 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जो राष्ट्रीय कर ढांचे में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) 31 मई, 2025 तक, भारत में 1.52 करोड़ से अधिक सक्रिय GST पंजीकरण दर्ज किए गए, जो बढ़ते कर आधार को दर्शाता है। ये आँकड़े भारतीय व्यवसायों और उद्यमियों के बीच कर अनुपालन और पंजीकरण में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

(ii) रिपोर्ट से पता चला है कि लगभग 20% (एक-पाँचवाँ हिस्सा) पंजीकृत करदाताओं में कम से कम एक महिला सदस्य है। इसके अतिरिक्त, लगभग 14% पंजीकृत करदाता पूरी तरह से महिलाओं के नेतृत्व वाली संस्थाएँ हैं, जो औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।

(iii) भारत में सकल GST संग्रह पिछले पाँच वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है - वित्त वर्ष 21 (2020-21) में 11.4 लाख करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 25 (2024-25) में लगभग 22.1 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो GST व्यवस्था के तहत कर राजस्व की मजबूत

वृद्धि और बेहतर अनुपालन को दर्शाता है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. दीपक बागला ने नीति आयोग में अटल नवाचार मिशन के निदेशक का पदभार ग्रहण किया।



21 जुलाई, 2025 को, इन्वेस्ट इंडिया के पूर्व एमडी और CEO दीपक बागला ने आधिकारिक तौर पर नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, वे डॉ. चिंतन वैष्णव का स्थान लेंगे।

- दीपक बागला को भारत सरकार के नीति थिंक टैंक, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग द्वारा नियुक्त किया गया है। वे डॉ. चिंतन वैष्णव का स्थान लेंगे, जो इससे पहले AIM में निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

- दीपक बागला ने अपना अंतर्राष्ट्रीय वित्त कैरियर विश्व बैंक (WB) से शुरू किया और बाद में 1989 में सिटी बैंक में शामिल हो गए। निजी इक्विटी और राष्ट्रीय निवेश में जाने से पहले उन्होंने एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका सहित कई क्षेत्रों में काम किया।

- 2015 में, उन्हें राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी, इन्वेस्ट इंडिया का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में, इन्वेस्ट इंडिया

ने कई वैश्विक मान्यताएँ अर्जित कीं और निवेश सुविधा एवं उद्यमिता में महत्वपूर्ण सुधार किए।

Key Points:-

(i) दीपक बागला ने भारत सरकार की कई शीर्ष-स्तरीय समितियों में कार्य किया है और विश्व निवेश संवर्धन एजेंसी संघ (WAIPA) के अध्यक्ष पद सहित कई वैश्विक पदों पर कार्य किया है। उन्हें इटली के राष्ट्रपति द्वारा इतालवी ऑर्डर "ग्रैंड उफिशियल डेल'ऑर्डिन डेला स्टेला डी'इटालिया" से सम्मानित किया गया था।

(ii) अटल नवाचार मिशन (AIM), नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की प्रमुख पहल है। इसमें अटल टिकरिंग लैब्स (ATLs), अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AICs), अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (ACICs) और अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस (ANIC) जैसी प्रमुख उप-पहलें शामिल हैं।

(iii) 2024 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एआईएम 2.0 को मंजूरी दी, और इसकी अवधि मार्च 2028 तक बढ़ा दी। सरकार ने इसके निरंतर संचालन और नवाचार बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2,750 करोड़ रुपये आवंटित किए।

2. पूर्व CBDT अध्यक्ष नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।



17 जुलाई, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने नितिन गुप्ता को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MoCA) के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। उनका कार्यकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रहेगा।

● नितिन गुप्ता ने रवनीत कौर से पदभार ग्रहण किया, जो अप्रैल 2025 से अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं। 31 मार्च, 2025 को अजय भूषण पांडे का तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद से यह पद रिक्त था।

● ACC ने स्मिता घिंगरन, पी. डैनियल और सुशील कुमार जायसवाल को एनएफआरए के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने की भी घोषणा की, जिससे नियामक निकाय की संरचना मजबूत होगी।

● नितिन गुप्ता आयकर संवर्ग के 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं। वे इससे पहले वित्तीय विनियमन और कराधान क्षेत्र में कई उच्च पदों पर कार्यरत रहे हैं।

Key Points:-

(i) नितिन गुप्ता ने 1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2024 तक वित्त मंत्रालय (MoF) के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कर प्रक्रियाओं को

डिजिटल बनाने और अनुपालन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(ii) CBDT में अपनी भूमिका से पहले, वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में महानिदेशक (DG) थे, जहां उन्होंने नीति प्रवर्तन और आर्थिक प्रशासन में अपने अनुभव को और मजबूत किया।

(iii) NFRA, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, का गठन 1 अक्टूबर, 2018 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत किया गया था। यह लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों की सिफारिश करने, अनुपालन की निगरानी करने, लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और आवश्यकता पड़ने पर लेखा परीक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है।

3. स्टीफन डेब्लेस सितंबर 2025 से CEO के रूप में रेनॉल्ट ग्रुप इंडिया का नेतृत्व करेंगे।



फ्रांसीसी ऑटो प्रमुख रेनॉल्ट समूह ने 21 जुलाई 2025 को घोषणा की कि स्टीफन डेब्लेस 1 सितंबर 2025 से भारत परिचालन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह भारत में सभी संस्थाओं में कंपनी की रणनीतिक दिशा को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

● अपनी नई भूमिका में, डेब्लेस भारत में रेनॉल्ट समूह की सभी संस्थाओं की देखरेख करेंगे और

रेनॉल्ट समूह के खरीद, साझेदारी और सार्वजनिक मामलों के प्रमुख, फ्रांस्वा प्रोवोस्ट को सीधे रिपोर्ट करेंगे। रेनॉल्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक, वेंकटराम मामिलपल्ले, अपनी वर्तमान भूमिका में बने रहेंगे और कॉर्पोरेट मामलों में डेब्लेस की सहायता करेंगे।

● दो दशकों से ज्यादा के वैश्विक अनुभव वाले रेनॉल्ट के एक अनुभवी दिग्गज, स्टीफन डेब्लेस ने लैटिन अमेरिका, चीन, फ्रांस और हाल ही में रेनॉल्ट कोरिया के सीईओ (2022 से) के रूप में नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं। उन्हें कोरिया को एक वैश्विक विकास केंद्र में बदलने और बहु-ऊर्जा वाहन उत्पादन के लिए बुसान संयंत्र के आधुनिकीकरण का श्रेय दिया जाता है।

● डेब्लेस की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब रेनॉल्ट इंडिया की यात्री वाहन बाज़ार में हिस्सेदारी लगातार घट रही है—वित्त वर्ष 2025 में यह घटकर 0.93% रह गई और बाज़ार में 14 साल से ज्यादा समय बिताने के बावजूद सिर्फ 38,636 इकाइयों की बिक्री हुई। रेनॉल्ट का लक्ष्य 2030 तक 5% बाज़ार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन और नई डस्टर एसयूवी सहित पाँच नए मॉडल लॉन्च करना है।

Key Points:-

(i) रेनॉल्ट इंडिया चेन्नई के ओरागदम में एक विनिर्माण संयंत्र संचालित करती है, जिसकी वार्षिक क्षमता 480,000 इकाइयों की है और यह देश भर में 350 से अधिक बिक्री और 450 सेवा टचपॉइंट वाले खुदरा और सेवा नेटवर्क द्वारा समर्थित है। यह नियुक्ति विद्युतीकरण और ब्रांड ओवरहाल पर केंद्रित एक व्यापक "रेनॉल्ट" परिवर्तन रणनीति के अनुरूप है।

(ii) नेतृत्व परिवर्तन के साथ-साथ, रेनॉल्ट इंडिया "रेनॉल्ट. रीथिंक" ब्रांड परिवर्तन के तहत एक नया, न्यूनतम हीरे के आकार का लोगो और विजुअल पहचान पेश कर रही है। यह रीब्रांडिंग आगामी वाहन

लॉन्च में दिखाई देगी, जो भारत में रेनॉल्ट के तकनीक-प्रधान और उपभोक्ता-केंद्रित उपस्थिति की ओर बदलाव को दर्शाता है।

AWARDS

1. लेवोन अरोनियन ने लास वेगास में फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता; भारत के अर्जुन और प्रगनानंद क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर रहे।



जुलाई 2025 में, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के ग्रैंडमास्टर (GM) लेवोन अरोनियन ने वर्ल्ड चैस इवेंट्स लिमिटेड द्वारा नेवादा के व्यान लास वेगास में आयोजित फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर 2025 के लास वेगास चरण में खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और भारतीय GMs की भी अच्छी-खासी भागीदारी रही।

- लेवोन अरोनियन ने फाइनल में अमेरिकी ग्रैंडमास्टर हैस मोके नीमन को 1.5-0.5 के स्कोर से हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ, अरोनियन को 200,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹1.7 करोड़) का इनाम मिला, जबकि दूसरे स्थान पर रहे नीमन को 140,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹1.2 करोड़) मिले।

- नॉर्वे के ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन, जो वर्तमान में विश्व में नंबर एक हैं, ने हिकारू नाकामुरा को हराकर इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल

किया। कार्लसन को 100,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹86 लाख) का पुरस्कार मिला, जिससे फ्रीस्टाइल शतरंज प्रारूप में सबसे मज़बूत सक्रिय खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति और मज़बूत हुई।

- भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम आठ में जगह बनाई, लेकिन अमेरिका के ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारूआना से हार गए। अर्जुन कुल मिलाकर छठे स्थान पर रहे और उन्हें 40,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹34 लाख) का इनाम मिला।

Key Points:-

(i) एक और उभरते हुए भारतीय शतरंज स्टार, आर. प्रज्ञानंदधा ने प्लेसमेंट राउंड में अमेरिका के वेस्ली सो को हराया। उन्होंने पहला गेम और क्लासिफिकेशन मैच दोनों जीतकर 7वें स्थान पर रहे और 30,000 अमेरिकी डॉलर (करीब ₹25 लाख) का इनाम जीता। गौरतलब है कि प्रज्ञानंदधा ने टूर्नामेंट के दौरान मैग्नस कार्लसन को भी दो बार हराया—एक बार ग्रुप स्टेज में और फिर क्लासिफिकेशन गेम में।

(ii) विदित गुजराती ने फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर 2025 के लास वेगास चरण में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने चार अन्य खिलाड़ियों के साथ संयुक्त 13वें स्थान पर अपना अभियान समाप्त किया और उन्हें 7,500 अमेरिकी डॉलर (लगभग 6.4 लाख रुपये) का भागीदारी पुरस्कार दिया गया।

(iii) फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 अपने गतिशील समय नियंत्रण और अपरंपरागत शुरुआती स्थितियों के लिए जाना जाता है, जो दुनिया भर की शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। भारत का प्रदर्शन विशेष रूप से उत्साहजनक रहा, जहाँ तीन भारतीय ग्रैंडमास्टर्स—अर्जुन, प्रज्ञानंद और विदित—ने दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धी खेल का प्रदर्शन किया।

2. वस्त्र मंत्रालय ने उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए 2024 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की घोषणा की।



राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7 अगस्त 2024 पर, वस्त्र मंत्रालय (MoT) ने बुनकरों और कुशल कारीगरों को प्रतिष्ठित संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों सहित 22 पुरस्कार प्रदान किए। यह पहल भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत और लाखों ग्रामीण आजीविकाओं में इस क्षेत्र के योगदान को उजागर करती है।

- तेलंगाना के दो बुनकरों, गजम नर्मदा और गुडा पवन, ने खूब वाहवाही बटोरी—एक ने तो ₹8 करोड़ का उल्लेखनीय कारोबार हासिल किया। उनका काम पारंपरिक बुनकर समुदायों की व्यावसायिक व्यवहार्यता को रेखांकित करता है।

- 15वीं सदी के कवि के नाम पर, संत कबीर पुरस्कार उन कुशल बुनकरों को सम्मानित करता है जो पारंपरिक शिल्पकला को बनाए रखते हैं। विजेताओं को एक स्वर्ण सिक्का, शॉल, प्रशस्ति पत्र और एक वर्ष में दस नए उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पाद विकसित करने के लिए ₹6 लाख का अनुदान दिया जाता है।

- हथकरघा उद्योग 35-45 लाख बुनकरों को रोजगार देता है, जिनमें से 70-72% महिलाएँ हैं। यह उद्योग सालाना ₹37,000 करोड़ का राजस्व और

₹2,500 करोड़ का निर्यात करता है, जो इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।

Key Points:-

(i) बुनकर और कारीगर उत्थान जैसे MoT कार्यक्रमों के तहत, जुलाई 2024 तक 100 क्लस्टरों में 3,600 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है। शिल्प दीदी महोत्सव ने दिल्ली हाट और आईएनए में प्रदर्शनियों सहित विपणन अवसरों के माध्यम से 100 महिला कारीगरों को और अधिक सशक्त बनाया है।

(ii) सरकार ने बुनकरों की बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिए GeM ऑनबोर्डिंग, डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर (DRC), हथकरघा उत्पादक कंपनियाँ और ई-कॉमर्स सहयोग जैसी योजनाएँ शुरू कीं। क्षेत्रीय उत्पादों को संरक्षण प्रदान करते हुए अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक सात GI टैग प्रदान किए गए।

3. 'मेरी पंचायत' ऐप ने सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए WSIS पुरस्कार 2025 चैंपियन पुरस्कार जीता।



जुलाई 2025 में, पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की संयुक्त पहल के तहत विकसित 'मेरी पंचायत' मोबाइल एप्लिकेशन को प्रतिष्ठित WSIS पुरस्कार 2025 चैंपियन पुरस्कार

से सम्मानित किया गया। इस ऐप को "सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री" के लिए WSIS एक्शन लाइन श्रेणी के अंतर्गत मान्यता दी गई।

- यह पुरस्कार आधिकारिक तौर पर 7 से 11 जुलाई 2025 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित पैलेक्सपो में आयोजित WSIS+20 उच्च-स्तरीय कार्यक्रम 2025 के दौरान प्रदान किया गया। NIC/MoPR की वरिष्ठ निदेशक सुनीता जैन ने भारत सरकार की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। नई दिल्ली में एक अलग समारोह आयोजित किया गया, जहाँ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (MoPR) ने औपचारिक रूप से WSIS चैंपियन प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

- 2023 में लॉन्च किया गया 'मेरी पंचायत' ऐप एक परिवर्तनकारी डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, जो पूरे भारत में 25 लाख से ज्यादा निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और लगभग 95 करोड़ ग्रामीण निवासियों को सशक्त बना रहा है। यह 2.65 लाख ग्राम पंचायतों (GPs) तक फैला है और ज़मीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत शासन उपकरण प्रदान करता है।

- यह एप्लिकेशन पंचायत बजट, प्राप्ति, व्यय, विकास योजनाओं, निर्वाचित पदाधिकारियों के विवरण और सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों जैसे महत्वपूर्ण डेटा तक रीयल-टाइम पहुँच प्रदान करके पारदर्शिता और सहभागी शासन सुनिश्चित करता है। नागरिक अपने मोबाइल उपकरणों से सीधे नागरिक सेवाओं की निगरानी कर सकते हैं।

Key Points:-

(i) इस ऐप का एक अनूठा पहलू सांस्कृतिक और भाषाई समावेशिता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता है। यह 12 से ज्यादा भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिससे नागरिकों को उनकी स्थानीय बोलियों में शासन सुलभ होता है और डिजिटल शासन में

विविधता को बढ़ावा मिलता है।

(ii) WSIS (विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन) पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के सहयोग से प्रदान किए जाते हैं। 2025 का संस्करण WSIS+20 की उपलब्धि को चिह्नित करता है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का समर्थन करने वाले डिजिटल उपकरणों के मूल्यांकन पर केंद्रित है।

(iii) यह पुरस्कार ज़मीनी स्तर पर विकास के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाने में भारत के बढ़ते नेतृत्व और 'मेरी पंचायत' जैसे बहुभाषी, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से समावेशी शासन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

App and Web Portal

1. मिज़ोरम ने वैश्विक सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए 'मिज़ो डायस्पोराहब' पोर्टल लॉन्च किया।



जुलाई 2025 में, मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिज़ोरम के आइजोल में आइजल क्लब में एक समर्पित कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक तौर पर 'मिज़ो डायस्पोराहब' पोर्टल लॉन्च किया। इस अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एक केंद्रीकृत संचार और कल्याण सहायता तंत्र बनाकर, भारत और विदेशों

में राज्य के बाहर रहने वाले मिज़ो समुदायों के साथ संबंधों और समन्वय को मजबूत करना है।

- मिज़ो डायस्पोराहब पोर्टल को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अंतर्गत मिज़ो डायस्पोरा प्रकोष्ठ द्वारा मिज़ोरम स्थित स्टार्टअप, लुशाएआईटेक प्राइवेट लिमिटेड के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। इसे दुनिया भर में रहने वाले मिज़ो लोगों के बीच पंजीकरण, अद्यतन जानकारी, संचार और आपातकालीन सहायता के लिए एक केंद्रीकृत, सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

- यह पोर्टल राज्य सरकार और प्रवासी समुदाय के बीच एक समर्पित डिजिटल सेतु का काम करता है, जो पंजीकृत मिज़ो कल्याण संघों के बीच संचार, समन्वय और संसाधन-साझाकरण को बेहतर बनाने के लिए उपकरण प्रदान करता है। यह मिज़ोरम के बाहर रहने वालों के साथ समय पर अपडेट और सहज संवाद सुनिश्चित करता है।

Key Points:-

(i) इस पहल का एक प्रमुख लक्ष्य सामूहिक कल्याण और पारस्परिक सहयोग प्रणालियों को मजबूत करना है। यह प्लेटफ़ॉर्म आपातकालीन स्थितियों में समन्वित प्रतिक्रियाएँ प्रदान करता है और विदेशों में चुनौतियों का सामना कर रहे मिज़ो लोगों, विशेष रूप से स्वास्थ्य, सुरक्षा या कानूनी मुद्दों, के लिए एक जीवनरेखा के रूप में कार्य करता है।

(ii) इस प्लेटफ़ॉर्म पर आधिकारिक रूप से पंजीकृत मिज़ो कल्याण संघों की एक निर्देशिका उपलब्ध है, जिसमें क्षेत्रीय सभा केंद्रों, पदाधिकारियों के संपर्क विवरण और कार्यक्रमों की सूची शामिल है। इसमें एक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस भी शामिल है जो प्रवासी सदस्यों द्वारा त्वरित पंजीकरण और डेटा अपडेट की सुविधा प्रदान करता है।

(iii) तकनीकी रूप से, पोर्टल को AI-सक्षम स्वचालित अनुवाद सेवाओं से उन्नत किया गया है, जो भाषा

संबंधी बाधाओं के बावजूद संचार सुनिश्चित करता है। इसमें एक SOS अलर्ट सुविधा (सेव आवर सोल्स) भी शामिल है जो उपयोगकर्ताओं को सिस्टम के माध्यम से सीधे आपातकालीन संकेत भेजने में सक्षम बनाती है, जिससे यह वास्तविक समय पर मदद और सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है।

IMPORTANT DAYS

1. Pi सन्निकटन दिवस 2025 गणितीय स्थिरांक π के उपलक्ष्य में 22 जुलाई को मनाया गया।



Pi सन्निकटन दिवस, जिसे कैजुअल Pi दिवस भी कहा जाता है, गणितीय स्थिरांक पाई (π) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन भिन्न 22/7 से जुड़े होने के कारण जाना जाता है, जो π के मान के लगभग बराबर है और जिसका गणित, इंजीनियरिंग और भौतिकी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

- Pi सन्निकटन दिवस पहली बार 1995 में स्वीडन के गोथेनबर्ग स्थित चाल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी में मनाया गया था, जिससे यह गणितीय समुदाय में अपेक्षाकृत नया लेकिन व्यापक रूप से सराहा जाने वाला आयोजन बन गया। इस उत्सव में आमतौर पर गणित से संबंधित खेल, शैक्षिक चर्चाएँ

और गणितीय परिशुद्धता के महत्व पर ज़ोर देने वाली गतिविधियाँ शामिल होती हैं।

- इस दिवस के लिए 22 जुलाई (22/7) की तिथि का चयन π के भिन्नात्मक सन्निकटन पर आधारित है— $22 \div 7$, जो लगभग 3.142857 के बराबर है, जो वास्तविक गणितीय स्थिरांक $\pi \approx 3.14159$ के बहुत करीब है। यह इस दिन को गणित शिक्षकों और छात्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

- पाई (π) एक अपरिमेय और पारलौकिक संख्या है जो वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को दर्शाती है। इसे परिमित दशमलव या भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यावहारिक गणनाओं के लिए आमतौर पर 3.14 या 22/7 जैसे सन्निकटनों का उपयोग किया जाता है।

Key Points:-

(i) π की पहली ज्ञात गणना प्राचीन यूनानी गणितज्ञ आर्किमिडीज़ ने की थी, जिन्होंने इसके मान का अनुमान लगाने के लिए उत्कीर्ण और परिवर्द्ध बहुभुजों वाली एक ज्यामितीय विधि का उपयोग किया था। उनके कार्य ने π की अधिक सटीकता से गणना करने के भविष्य के संख्यात्मक तरीकों की नींव रखी।

(ii) गणितीय स्थिरांक के प्रतीक के रूप में ग्रीक अक्षर " π " का प्रयोग सबसे पहले 1706 में वेल्श गणितज्ञ विलियम जोन्स ने किया था। 1737 में स्विस् गणितज्ञ लियोनहार्ड यूलर द्वारा इसे लोकप्रिय बनाए जाने के बाद इस संकेतन को व्यापक मान्यता मिली और अब यह वैश्विक गणितीय साहित्य में एक मानक प्रतीक है।

(iii) पाई सन्निकटन दिवस, वैज्ञानिक प्रगति और दैनिक समस्या-समाधान में गणित की भूमिका की याद दिलाता है। यह उत्सव 14 मार्च (3/14) को मनाए जाने वाले पाई दिवस का भी पूरक है, जो अमेरिकी तिथि प्रारूप पर आधारित है और π की स्थायी प्रासंगिकता को उजागर करने के लिए एक और अवसर है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. भारतीय सेना को अमेरिका से AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच प्राप्त हुआ।



22 जुलाई, 2025 को, भारतीय सेना (IA) को संयुक्त राज्य अमेरिका से तीन एच-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए, जो 2020 में हस्ताक्षरित छह-हेलीकॉप्टर सौदे के तहत पहली डिलीवरी थी। विमानों को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन वायु सेना स्टेशन में शामिल किया गया, जिससे भारत की लड़ाकू विमानन क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला।

- यह आपूर्ति भारत सरकार द्वारा 2020 में अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध का हिस्सा है, जिसके तहत विशेष रूप से भारतीय सेना के लिए छह AH-64E अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर बोइंग द्वारा विकसित अपाचे श्रृंखला के नवीनतम मॉडल हैं और पहली बार सेना विमानन कोर में शामिल किए जा रहे हैं।

- नए वितरित हेलीकॉप्टरों को राजस्थान के जोधपुर के पास नागटालू स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह भारतीय सेना द्वारा अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली परिचालन तैनाती है, जबकि भारतीय वायु सेना (IAF) पहले से ही एक अलग सौदे के तहत वितरित 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों के बेड़े का संचालन कर रही है।

● शुरुआत में जून 2024 में इनकी डिलीवरी होनी थी, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और तकनीकी देरी के कारण इसे जुलाई 2025 तक के लिए टाल दिया गया। शेष तीन अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी नवंबर 2025 तक होने की उम्मीद है, जिससे छह इकाइयों का पूरा ऑर्डर पूरा हो जाएगा।

Key Points:-

(i) AH-64E अपाचे अपनी उन्नत युद्धक्षेत्र क्षमताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उच्च-तीव्रता वाले युद्ध में संलग्नता, उत्तरजीविता और लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाना शामिल है। इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स, रात्रि-दृष्टि प्रणाली और बहु-मिशन आक्रमण क्षमताएँ हैं, जिसके कारण जटिल युद्ध स्थितियों में इसके मज़बूत प्रदर्शन के लिए इसे "उड़ने वाला टैंक" उपनाम दिया गया है।

(ii) तकनीकी रूप से, AH-64E में 30 मिमी M230 चैन गन, AGM-114 हेलफायर मिसाइलें और हाइड्रा 70 रॉकेट पॉड्स शामिल हैं। यह दो जनरल इलेक्ट्रिक T700-GE-701D इंजनों द्वारा संचालित है और ड्रोन के साथ रीयल-टाइम डेटा साझा करने के लिए MUM-T (मानव-मानव रहित टीमिंग) को सपोर्ट करता है। इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम गति 293 किमी/घंटा और परिचालन सीमा 480 किमी है।



जुलाई 2025 में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने भारत के पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन उम्मीदवार 'AdFalcivax' के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) के लिए पात्र कंपनियों से रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) आमंत्रित की, जिसका उद्देश्य मलेरिया से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन और तैनाती करना है।

● AdFalcivax को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ICMR -क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र (ICMR-RMRC), ICMR-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (ICMR-NIMR), और जैव प्रौद्योगिकी विभाग-राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (DBT-NII) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह टीका स्वदेशी नवाचार के माध्यम से मलेरिया उन्मूलन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है।

● AdFalcivax भारत में पहला पुनः संयोजक काइमेरिक बहु-चरण मलेरिया टीका है, जिसे प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम - जो मनुष्यों में मलेरिया पैदा करने वाला सबसे घातक परजीवी है - के प्री-एरिथ्रोसाइटिक (यकृत) चरण और यौन (मच्छर-संचरण) चरण दोनों को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

● यह टीका एक नवीन पुनःसंयोजक काइमेरिक तकनीक का उपयोग करता है जो विशिष्ट प्रतिजनों को मिलाकर एक व्यापक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न

2. ICMR ने भारत के पहले मलेरिया वैक्सीन 'AdFalcivax' के व्यावसायिक उत्पादन के लिए EoI आमंत्रित किया।

करता है। इसे लैक्टोकोकस लैक्टिस नामक एक खाद्य-ग्रेड बैक्टीरिया का उपयोग करके तैयार किया गया है, जो इसे व्यावसायिक जैव-निर्माण के लिए सुरक्षित, मापनीय और प्रभावी बनाता है।

Key Points:-

(i) प्रीक्लिनिकल पशु अध्ययनों से आशाजनक परिणाम मिले हैं, और प्रमाण बताते हैं कि AdFalcivax मौजूदा एकल-चरण टीकों की तुलना में अधिक व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली के नष्ट होने की संभावना को कम करता है और संभावित रूप से दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिससे यह मलेरिया नियंत्रण में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होता है।

(ii) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) निजी निर्माताओं को टीके का प्रायोगिक और औद्योगिक उत्पादन शुरू करने की अनुमति देगा। इच्छुक कंपनियों को मलेरिया उन्मूलन रोडमैप का हिस्सा बनने के लिए ICMR द्वारा निर्धारित विशिष्ट पात्रता और गुणवत्ता मानकों को पूरा करना होगा।

(iii) यह कदम भारत के व्यापक स्वास्थ्य नीति लक्ष्यों का समर्थन करता है, जिसमें मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ढाँचा (NFME) भी शामिल है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की मलेरिया 2016-2030 के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति के अनुरूप है। भारत का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन करना है और AdFalcivax इस लक्ष्य को प्राप्त करने में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है।

OBITUARY

1. केरल के वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता वी.एस. अच्युतानंदन का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया।



केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ CPI (M) नेता, वी.एस. अच्युतानंदन के नाम से प्रसिद्ध वेलिककाथुशंकरन अच्युतानंदन का लंबी बीमारी और अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 21 जुलाई 2025 को 101 वर्ष की आयु में तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया।

● अच्युतानंदन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के अंतिम जीवित संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और केरल विधानसभा में लगभग 15 वर्षों तक सेवा करते हुए, सबसे लंबे समय तक विपक्ष के नेता का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे सात बार विधानसभा के लिए चुने गए।

● अपनी अटूट निष्ठा के लिए जाने जाने वाले वी.एस. ने भ्रष्टाचार, भूमि अतिक्रमण, लॉटरी माफिया और फिल्म पाइरेसी के खिलाफ कई अभियानों का नेतृत्व किया। उनकी सरकार ने अवैध रूप से कब्जा की गई ज़मीन वापस दिलाई और शिक्षा में मुफ्त सॉफ्टवेयर का समर्थन किया—ऐसे कार्यों के कारण उन्हें एक दृढ़ जन-हितैषी नेता के रूप में सार्वजनिक ख्याति मिली।

Key Points:-

(i) 20 अक्टूबर 1923 को पुन्नपरा, अलपुझा में एक खेतिहर मज़दूर परिवार में जन्मे, उन्होंने 1940 के

दशक में एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की। वे 1940 में कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल हुए, भूमिगत गतिविधियों के दौरान गिरफ्तारियाँ झेलीं और 1964 में माकपा के गठन के बाद एक प्रमुख नेता बन गए।

(ii) जून 2025 के अंत में हृदयाघात के बाद, अच्युतानंदन को तिरुवनंतपुरम के एसयूटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे जीवन रक्षक प्रणाली पर रहे और डॉक्टरों द्वारा उनकी निरंतर निगरानी की गई। 21 जुलाई 2025 को आयु संबंधी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया।

Static GK

Kerala	मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन	राज्यपाल: राजेंद्र आर्लेकर
Malaysia	प्रधान मंत्री: अनवर इब्राहिम	आधिकारिक भाषा: मलय
NITI Aayog	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम	मुख्यालय: नई दिल्ली
Indian Army	थल सेनाध्यक्ष (COAS): जनरल उपेंद्र द्विवेदी	मुख्यालय: नई दिल्ली
SBI	अध्यक्ष: चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी	मुख्यालय: मुंबई